E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2025; 7(2): 112-114
Received: 09-12-2024
Accepted: 13-01-2025

डॉ. आलोक राज
पूर्व शोधार्थी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा कोसी कॉलोनी, पूर्णिया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. आलोक राज
पूर्व शोधार्थी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा कोसी कॉलोनी, पूर्णिया, बिहार, भारत

एक राष्ट्र एक चुनाव: भारतीय दृष्टिकोण से एक अध्ययन

आलोक राज

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2025.v7.i2b.1370

सारांश
लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है और यह वह समाज है जिसमें नागरिक सर्वोच्च होते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं। चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष होना लोकतंत्र की कुंजी है। चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक समाज की मौलिक विशेषता है, क्योंकि यह नागरिकों की राष्ट्र के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करती है। हम जानते हैं कि भारत में, चुनाव आमतौर पर हर साल कुछ राज्यों में होते हैं, और इस कारण विकास प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि आचार संहिता लागू होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे वर्ष चुनावों को रोकने की क्षमता रखता है, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य विचार लोकसभा और विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। 2015 की संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट के अनुसार, एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत सरकार के चुनावी खर्चों में लाखों रुपये बचाता है, जब लोकसभा और राज्य विधानसभाएं एक साथ होती हैं।

कुटशब्द: लोकतंत्र, समाज, भारत, लोकसभा, चुनाव

प्रस्तावना
लोकतंत्र को संचालित करने के लिए चुनाव सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। भारत में हर साल एक या एक से अधिक राज्यों में चुनाव होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की एक नई अवधारणा के तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनावों में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव सभी राज्यों में विभिन्न चरणों में एक साथ आयोजित किए गए। हम जानते हैं, भारतीय संविधान में, हर पांच साल के बाद सभी स्तरों पर चुनाव होते हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव राज्य और केंद्र स्तर पर एक साथ आयोजित किए जाते हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए एकल चुनाव आयोजित करने की विधि है, इस तरह के ढांचे में अलग-अलग और निरंतर चुनाव के बजाय मतदाता एक ही समय में राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डालते हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव विनियमन के अनुसार आयोजित किए जाते हैं और चुनाव आयोग सुरक्षित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होता है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के मुद्दे की उत्पत्ति
दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधायी चुनाव हर पांच साल में होते हैं, जिसके दो साल बाद नगरपालिका चुनाव होते हैं। स्वीडन में, राष्ट्रीय विधानमंडल (रिक्सडैग) प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी परिषद (लैंडस्टिंग) और स्थानीय निकायों/नगरपालिका विधानसभाओं (कोम्मुनफुलमाक्टिगे) के लिए चुनाव एक विशिष्ट तिथि के लिए निर्धारित किए जाते हैं- सितंबर में दूसरा रविवार-हर चार साल में। उदाहरण के लिए, पिछला चुनाव 14 सितंबर, 2014 को हुआ था।
इस बीच, U.K. में, संसद की अवधि 2011 के निश्चित अवधि के संसद अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। स्वतंत्रता के बाद, समय से पहले होने वाले आम चुनाव राज्य विधानसभा चुनावों के साथ हुए। यह 1967 तक जारी रहा, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ। 2014 में, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक धन के व्यर्थ खर्च पर अंकुश लगाने और आदर्श आचार संहिता द्वारा अक्सर बाधित विकास कार्यों में निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने की क्षमता का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराए।
अगस्त 2018 में, भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की वकालत करते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इसने इस समन्वय को सक्षम करने के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया। आयोग ने इन संशोधनों के लिए कम से कम 50% राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता पर जोर दिया। एक साथ चुनावों के फायदों पर प्रकाश डालते हुए, इसने सार्वजनिक धन में बचत, प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर कम दबाव, सरकारी नीतियों के समय पर निष्पादन और चुनाव प्रचार के बजाय

विकासात्मक गतिविधियों की ओर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

चुनाव आयोग

भारत में, भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो संघ और राज्य चुनावों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 और 25 जनवरी को हुई थी, जिसे हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329) चुनाव विषयों से संबंधित आयोग के चुनाव और स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित हैं:

अनुच्छेद 324: निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित किया जाएगा।

अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, नस्ल या जाति के आधार पर विशेष मतदाता सूची में अयोग्य या शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव।

अनुच्छेद 327: प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति विधायिका के चुनाव के संबंध में।

अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को बनाने की शक्ति राज्य विधायी के संबंध में प्रावधान

अनुच्छेद 329: निर्वाचन में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक बातें

चुनाव आयोग की भूमिका

1. पूरे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर।
2. मतदाता सूची तैयार करना और मतदाताओं का पंजीकरण करना।
3. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनके प्रतीक और उन्हें राष्ट्रीय या दर्जा का दर्जा प्रदान करें
4. पार्टी।
5. उम्मीदवार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आचरण की भूमिका निर्धारित करें पार्टी भी।
6. सांसद की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देना और क्रमशः विधायक की अयोग्यता पर राज्यपाल।
7. चुनाव कार्यक्रम प्रदान करने के साथ-साथ निर्धारित करने के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव व्यय।

चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां

1. चुनाव में बढ़ रही हिंसा
2. ईवीएम में खराबी
3. अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के लिए बहु मतदाता पहचान पत्र राज्यों
4. चुनाव में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबरें और चुनाव
5. बूथ कैप्चरिंग और वोट हाइजैकिंग
6. चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल
7. वोटों के लिए नकद और मतदाताओं को रिश्वत के रूप में उपहार में दी गई वस्तुएं वोटों के लिए
8. राजनीतिक दलों द्वारा चुनवी पुरस्कारों की घोषणा
9. चुनाव में महिलाओं की कम भागीदारी
10. नामांकन प्रपत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरा गया गलत विवरण (उम्मीदवार अवैध धन और संपत्ति नहीं दिखाते हैं नामांकन फॉर्म)
11. उचित प्रशिक्षित प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा, जो चुनाव की अवधि को लंबा बनाती है

एक राष्ट्र एक चुनाव

एक रिपोर्ट में, संसदीय समिति ने बताया कि यदि सभी चुनाव के प्रकार देश में एक बार में आयोजित किए जाते हैं, नहीं इससे चुनाव आयोग पर बोझ कम होगा लेकिन राजनीतिक दलों का खर्च भी कम हुआ। आज एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा का विषय नहीं है, यह एक मुद्दा है भारत की समकालीन आवश्यकता, जैसा कि हम हर साल जानते हैं देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं। लगातार होने वाले चुनावों का प्रशासनिक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है।

अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को विनियमित किया जाता है तो देश को एक नई दिशा मिलेगी क्योंकि कई बार और बार-बार चुनाव में खर्च होने वाले पैसे की बचत होगी और यह देश के विकास के लिए बचत धन का उपयोग।

टेबल-1: चुनावों में कुल व्यय

Year	कुल व्यय (करोड़ में)
1998	9000
1999	10000
2004	14000
2009	20000
2014	30000
2019	60000

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा संकलित

एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ

1. इससे लोकसभा को पांच साल का कार्यकाल पूरा करने में मदद मिलेगी
2. समय की बचत
3. चुनाव में लागत कम करें और पैसे बचाएं
4. विकास पर अधिक ध्यान दें-क्योंकि ज्यादातर समय विकास में व्यतीत होता है।
5. चुनाव में सेवा क्षेत्र के व्यवधान को कम करना- अधिकतर शिक्षक और अन्य सरकारी अधिकारी हैं चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जो व्यवधान का कारण बनती है
6. अर्धसैनिक बलों पूरे साल चुनाव शामिल होते हैं और अगर एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के बाद, अगले पाँच वर्षों तक चुनाव कर्तव्यों का कोई बोझ नहीं होगा।
7. सभी हितधारकों को अधिक समय प्रदान करें i.e. राजनीतिक दल, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) तैयारी के लिए अर्धसैनिक बल, नागरिक।

एक राष्ट्र एक चुनाव के नुकसान

1. संविधान में संशोधन की जरूरत
2. यदि केंद्र और राज्य स्तर पर हर पांच साल में चुनाव एक साथ होते हैं, तो राजनेताओं और जनता के बीच बातचीत कम सक्रिय होती है।
3. चुनावों के लिए बड़ी संख्या में प्रशासनिक स्टाफ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
4. हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में, मतदाताओं का केंद्र और राज्य स्तर पर चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक व्यवहार होता है, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के बाद उनके लिए उम्मीदवार चुनना बहुत कठिन हो जाता है।

5. यह राज्य की राजनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
6. सभी राजनीतिक दलों को इस विचार पर मनाने और एकजुट करने में कठिनाई होती है।
7. समानांतर चुनाव आयोजित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) की आवश्यकताएँ दोगुनी हो जाएँगी क्योंकि ECI को दो सेट प्रदान करने होंगे (एक विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए)।
8. राष्ट्रीय पार्टियाँ राज्य स्तर पर छोटी पार्टियों की आवाज़ को दबा सकती हैं क्योंकि उनके पास अधिक प्रभाव होता है।
9. छोटी पार्टियाँ जो राज्य के लोगों की क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए बनी थीं, उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाएगा।

आगे का रास्ता

हालांकि एक साथ चुनाव कराने के विचार में भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। कई गंभीर वैधानिक और संवैधानिक संशोधन हैं जिन पर इस संदर्भ में बहस और चर्चा की आवश्यकता है। इस संबंध में किसी भी नीतिगत कदम के लिए राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक राजनीतिक स्पेक्ट्रम के हितधारकों के बीच सामान्य सहमति की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यदि सत्तारूढ़ दल या गठबंधन सरकार लोकसभा या राज्य चुनावों में बीच-बीच में बहुमत खो देती है तो दीर्घकालिक स्थिरता का भी सवाल है। ऐसे परिदृश्य में, संसदीय स्थायी समिति 6 द्वारा सुझाए गए दो-चक्र चुनाव प्रक्रिया एक बेहतर उद्देश्य की पूर्ति करेगी, जिसमें एक चरण लोकसभा चुनाव के साथ और दूसरा चरण पहले चरण के ठीक 30 महीने बाद हो सकता है। इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से निकट भविष्य में देश में चुनावों की वर्तमान आवृत्ति को कम करेगी, जिससे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण में नियमित बाधाओं को कम किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

भारत का संविधान मौलिक रूप से राज्य शासन की एक संघीय संरचना प्रदान करता है। कई सरकारी स्तर हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा राज्य सरकारें, नगर निगम और पंचायतें हैं। शक्ति एक हाथ में नहीं है, यह विभिन्न सरकारी स्तरों में विभाजित है, जबकि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है, तो शक्ति एक हाथ में होती है। यदि इसे नियमों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन के साथ किया जा सके, तो यह भारतीय चुनाव प्रणाली में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है, जिसमें अच्छे प्रशासनिक कर्मचारियों और सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। "स्थायी समिति ने कहा है कि भारत में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए समाधान खोजे जाने चाहिए ताकि सरकारी मशीनरी, साथ ही चुनाव आयोग, अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ समय प्राप्त कर सके। बेहतर लोकतांत्रिक विकास के लिए हमें चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण और कंप्यूटरीकृत मतदान जैसे सुधारों के बारे में भी सोचना चाहिए और मतदाता की गोपनीयता प्रदान करनी चाहिए।

संदर्भ

1. https://eci.gov.in/
2. https://www.bloomberg.com/india
3. https://www.cmsindia.org/
4. legislative.gov.in/constitution-of-India
5. बंसल। एम. (2019) एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, भारतीय परिप्रेक्ष्य से एक विश्लेषण। भारत के बारे में सोचिए। Vol.22 (4) 2.
6. भगत पी. और पोखरियाल। पी. (2020) अवधारणात्मक सुधार एक राष्ट्र एक चुनाव। प्रारंभिक शिक्षा ऑनलाइन।
7. घई के. (2008) भारतीय सरकार और राजनीति। कल्याणी पब्लिशर्स
8. गोविंदराज एम. और सिंह। एन. (2001) भारत में संघवादः राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सुधार। मिशिगन विश्वविद्यालय।
9. पाईली एम. (2023) भारतीय संविधान। एस. चंद्रा एंड कंपनी लिमिटेड
10. शिवानी। (2021) एक राष्ट्र एक चुनावः भारत में एक नया चुनावी सुधार। सुप्रीम एमिकस, वॉल्यूम. 24.
11. सुधा। यू. (2020) लोकतांत्रिक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा। शोध संचार बुलेटिन। Vol.10 (4)